Statement

Sl. No.	State/U.T.	Provision (Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	7100.00
2.	Arunachal Pradesh	869.00
3.	Assam	3846.00
4.	Bihar	5250.00
5.	Goa	375.00
6.	Gujarat	5621.00
7.	Haryana	2240.00
8.	Himachal Pradesh	4128.00
9.	Jammu & Kashmir	3550.70
10.	Karnataka	4750.00
11.	Kerala	4860.00
12.	Madhya Pradesh	48.00.00
13.	Maharashtra	9567.00
14.	Manipur	820.00
15.	Meghalaya	1250.00
16.	Mizoram	300.00
17.	Nagaland	389.00
18.	Orissa	3385.00
19.	Punjab	2250.00
20.	Rajasthan	5522.00
21.	Sikkim	372.00
22.	Tamil Nadu	7713.00
23.	Tripura	733.00
24.	Uttar Pradesh	7648.00
25.	West Bengal	2952.00
26.	A & N Islands	350.00
27.	Daman & Diu	38.00
28.	Lakshadweep	70.00
29.	Pondicherry	59.00
30.	Delhi	450.00
31.	D & N Haveli	61.00
32.	Chandigarh	———
	Total :	91324.40

गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

7082. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिलेवार ब्योरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिये कोई अलग आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, ग्रामीण सड़कों का निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक अनुमेय मद है जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और ग्राम पंचायतों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों के अपने अंश में से स्वयं किया जा सकता है।

"कापार्ट" को उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

7083. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कापार्ट) को उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए धनराशि

7084. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने हेतु वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा प्रदान की गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या सरकार योजनागत परिव्यय में वृद्धि करने का विस्तार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने हेतु निधियां, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को उद्यतन करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत रिलीज की जाती हैं। योजना के अंतर्गत 1990–91 और 1991–92 के दौरान रिलीज की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। *(नीचे देखिए)*

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक इस योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज हेतु प्रस्ताव केवल अरुणाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है जिसपर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) योजना के अंतर्गत योजना परिव्यय में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20.81 करोड़ रुपए की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि करके इसे 175.00 करोड़ रुपए किया गया है। चालू वर्ष (1994–95) में इस योजना के लिए 27.47 करोड़ रुपए हैं। इस समय 8वीं पचवर्षीय योजना परिव्यय में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1990-91 और 1991–92 के दौरान राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश के रूप में निधियों की रिलीज

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई निधियां	
		1990-91	1991-92
1.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	—
2.	असम	50.00	—
3.	बिहार	150.00	—